

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 136/2022

जडाई देवी पत्नि कुरडा राम, जाति जाट, निवासी ओजटू, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं।

— रेस्पोजेन्ट

प्रथम अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं, मुकदमा उनवानी सरकार बनाम जडाई देवी, अ0धा0 91, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, मु0न0 08/2022, निर्णय दिनांक 30.06.2022


उपस्थित:-

1. श्री अशोक लाम्बा, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोजेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 22.09.2022


पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 30.06.2022 के विरुद्ध मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्त के अनुसार अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनूं ने अपीलान्त को आराजी हाल खसरा नं0 94 रकबा 4.07 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड ओजटू तहत तहसील चिडावा मे से 0.03 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 30.06.2022 को पारित किया। इस कारण अपीलान्त की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्त अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्त के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। निर्णय जैर बहस स्वीकृति नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत जबाब को बिना डिस्कस किये निर्णय पारित किया है। निर्णय जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट है। अपीलान्त के तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे व निर्णय जैर बहस मे दर्ज नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय रिपोर्ट साबित नहीं की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत ने एकपक्षीय पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने मे कानूनी गलती की है। अपीलान्त के हक मे विभाग के द्वारा सनद 20.01.2001 से विधुत कनेक्शन स्थापित है। अदालत मातहत के अपीलान्त ने


जिला कलक्टर झुंझुनूं

उपरोक्त बिन्दू को रखा था व इजाजतन कब्जे को एक सारवान बिन्दू उठाया था। कानून से जब कोई सारवान बिन्दू उठाया जाता है तो उस सूरत में समरी प्रोसेडिंग के मार्फत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत ने उपरोक्त कानूनी स्थिति को नजरअंदाज किया है। अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही करने में कानूनी गलती की है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से जोहड की नहीं है और ना ही जोहड के काम में आई है। अदालत मातहत ने भौतिक स्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त का पुराना कब्जा होना एक स्वीकृत तथ्य है। इस बाबत पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्त के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 को अपास्त किया जावे।

बहस वकील अपीलान्त सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्त के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत जबाब को बिना डिस्कस किये निर्णय पारित किया है। निर्णय जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट है। अपीलान्त के तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौड़ाई पटवारी हल्का की रिपोर्ट में व निर्णय जैर बहस में दर्ज नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय रिपोर्ट साबित नहीं की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत ने एकपक्षीय पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। अपीलान्त के हक में विधुत विभाग के द्वारा सनद 20.01.2001 से विधुत कनेक्शन स्थापित है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्त ने उपरोक्त बिन्दू को रखा था व इजाजतन कब्जे को एक सारवान बिन्दू उठाया था। कानून से जब कोई सारवान बिन्दू उठाया जाता है तो उस सूरत में समरी प्रोसेडिंग के मार्फत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत ने उपरोक्त कानूनी स्थिति को नजरअंदाज किया है। अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही करने में कानूनी गलती की है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से जोहड की नहीं है और ना ही जोहड के काम में आई है। अदालत मातहत ने भौतिक स्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त का पुराना कब्जा होना एक स्वीकृत तथ्य है। इस बाबत पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्त के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्त मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने ग्राम ओजटू स्थित सरकारी भूमि ख0न0 94 रकबा 4.07 हैक्टर किस्म गैर जोहड में से 0.03 है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म जैर मुमकीन जोहड है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। धारा 91 समरी प्रोसेडिंग है। अदालत

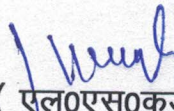

जिला वकीलक्टर झुन्झुनू

104/2

मातहत मे अपीलान्ट की जबाबदेही हुई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम ओजटू स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 94 कुल रकबा 4.07 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से 0.03 है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि गै0मु0 जोहड की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट को गै0मु0 जोहड की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 यथावत रखा किया जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं